छत्तीसगढ़ के ग्रामीण महिलाओं की शैक्षणिक स्थितियों का मुल्यांकन

डॉ. सुस्मिता सेन

सहायक प्राधायपक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा समस्या और संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है। वैदिक युग से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है। शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। एक विद्वान का कथन है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है एवं उसे उचित व्यवहार करने में प्रवृत्त करता है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के जिन प्रमुख तत्वों तथा विशेषताओं को हम पहले वर्णन कर चुकें है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दीर्घ अतीत में हमारे देश में शिक्षा की अति सुंदर व्यवस्था थी। शिक्षा का कर्तव्य था व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना । शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी मानसिक शक्तियों तथा क्षमताओं का विकास, उसके जीवन के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या और उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में आत्मिक उत्थान करने में सहायता देती हैं। अध्ययन के लिए गुरूकुल, आश्रम, गुरूगृह, संघ, चरण परिषद ये सभी संस्थाऐं थी ।

इसमें ब्राम्हणों को धर्म कर्म की, क्षत्रिय को युद्ध विद्या व राजनीतिक की वैश्यों को वाहणज्य की कृषि विज्ञान की तथा शूद्रों को हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि मौखिक थी अध्यापक छात्रों के प्रति पुजवत व्यवहार करते थे। छात्र गुरु की सेवा करते थे । बौद्ध धर्म में एक नवीन शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के समान होते हुए भी कुछ बातों में भिन्न थी । बौद्ध धर्म का विकास संघों के रूप में हुआ था । अतः बौद्ध शिक्षा के प्रमुख भारत केन्द्र "संघ" ही थें।

बौद्ध धर्म ने चारों जातियों के व्यक्तियों को स्थान दिया । में वैदिक धर्म के पुनरूत्थान के कारण बौद्ध धर्म का हास होता गया । पर शिक्षा के क्षेत्र में ब्राम्हणीय एकमात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों में मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने लोगों में जन सामान्य की शिक्षा की इच्छा का कुछ विस्तार किया और उस मांग को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण सार्वजनिक शिक्षा का विकास हुआ। भारत में लगभग साढ़े पांच सौ साल तक मुसलमानों का शासन रहा। इस काल में एक नवीन प्रणाली प्रस्फुटित हुई। जिसे मुस्लिम शिक्षा की संज्ञा दी जाती हैं। मुस्लिम युग में शिक्षा की व्यवस्था मकबरों और मदरसों में की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था मकबरों में थी और स्कूली शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में थी । लौकिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी इस काल में स्त्री शिक्षा, सैनिक शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी। मुस्लिम युगीन भारत की शिक्षा पर आलोचनात्मक दृष्टिपात करने से यह निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध होती हैं। कि उस युग की शिक्षा प्रणाली में लचीलेपन का अभाव था।

अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए एक अद्वितीय वरदान बनकर आई। अंग्रेजी के अध्ययन से ही प्राचीन कालीन युगों में परिवर्तन हुआ । पाश्चात्य साहित्य, शिक्षा तथा विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीयों ने देश में सर्वतोन्मुखी सुधा की ज्योति को जाग्रत किया । धर्मान्धता एवं बुद्धिहीन श्रद्धा का स्थान विवेक तथा तर्क ने ग्रहण किया । पाश्चात्य देशों में प्रतिपादित समाना स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के सिद्धांतों ने हमारे देश पर अमिट छाप लगा दी हैं। मध्यप्रांत में 1853 ई. के पूर्व शिक्षा पद्वति पुराने केवल ब्राम्हण पंडितों एवं मुल्लाओं के हाथ में था ब्रिटिश शासनकाल मे शिक्षा का प्रसार योजनाबद्ध पद्धति से होने लगा स्त्री की ओर भी ध्यान दिया गया 1837 की क्रांति के बाद विविध प्रकार के सुधार प्रारंभ हुए। वर्तमान समय में जब से मध्य से विभक्त होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है।

अतः 1 नवम्बर 2000 से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में सरकार द्वारा शिक्षा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है तथा वर्तमान समय में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया गया हैं। तथा उन योजनाओं में सरकार की सफलता एवं असफलता का भी उल्लेख किया गया हैं । तथा शिक्षा के द्वारा प्रदेश के नागरिकों का किस प्रकार विकास हो रहा है। इस शोध में सभी

बातों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया हैं उपरोक्त सुझाव पर यदि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी तथा छत्तीसगढ़ में साक्षरता की दर बढ़ेगी और राज्य में स्कूली शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी एवं राज्य के नागरिक अधिक से अधिक शिक्षित हो सकेंगें। संक्षेप में शिक्षा सामाजिकता को दृढ़ बनाती है। समाज के मौलिक एवं आध्यत्मिक विकास में प्रगति लाती हैं, समाज में नवजीवन का संचार करती है, इसलिए शिक्षा का उत्तरदायित्व परिवार से समाज पर आया और जब समाज राष्ट्र का संगठन करने में सफल हुआ तब आज नागरिकों को शिक्षित करना राज्य का उत्तरदायित्व समझा जा रहा हैं। क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी मनोकुल सांचे में ढाला जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालय एवं चिकित्सा अध्ययन का प्रयास किया गया है। आज के समय में कई युवक युवतियां है जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करके भी बेरोजगार है सरकार को चाहिए कि रोजगार मूलक अर्थात् ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे रोजगार प्राप्त हो सके ।

प्रदेश की सरकार द्वारा कई निजी विद्यालय भी खोले गयें हैं, इससे शासकीय विद्यालयों का भार कम होता है, यह एक अच्छा प्रयास है किन्तु सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निजी विद्यालयो की शिक्षा व्यवस्था जहां करें उन विद्यालयों में पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद के मैदान आदि है या नहीं क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए इस सभी तत्वों की आवश्यकता है। क्योंकि कई निजी विद्यालय या ऐसे है जो केवल कुछ कमरों में ही सीमित हैं। जब विद्यार्थी को उचित माहौल ही नहीं मिलेगा तो वह अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं कर पायेगा। इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योकि शिक्षा का स्तर निम्न नहीं होना चाहिए। इस ओर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए कि निजी विद्यालयों की भीड़ से क्या आज के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं इसके लिए विशेष विचार मंथन की आवश्यकता है। और सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे भी रही हैं।

राज्य बनने के बाद से पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ठ एवं अलग पहचान और विश्वसनीयता स्थापित की हैं। शिक्षा में अधोसंरचना एवं गुणात्मक विकास से समाज में लोगों के जीवनस्तर में उन्नयन हुआ हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश शीघ्र

ही देश में शिक्षा की धूरी बनने की ओर अग्रसर है। शासन द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु कई योजनाओं का संचालन किया है। एवं इसके परिणाम भी आने लगे है । भविष्य में भी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए प्रदेश प्रतिबद्ध रूप से नितनवीन योजनाओं प्रविधियों का क्रियान्वयन करेगी।

सभी पढ़े सभी बढ़े एवं एक भी बच्चा एवं नागरिक जब एक शिक्षा से वंचित है, तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। शिक्षा से वंचितहो जाना यह एक बड़ी चुनौती हैं। शिक्षा विभाग के लिए यह कार्य एक अभियान के समान है एवं सभी के सक्रिय प्रयासों से शिक्षा धारा सतत् प्रभावित होती रहेगी एवं समाज का प्रत्येक वर्ग इक्कीसवीं सदी में होने वाले अनुसंधानों का लाभ उठा पायेगा एवं बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकेगा। यही हमारा ध्येय एवं लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति में प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण, माध्यमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधियिम 2009 तथा साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

साथ ही प्रदेश की आधी जनसंख्या बालिका एवं महिलाओं की है, इनके भागीदारी के बिना शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य नही होता हैं। समाज के सक्रिय पहल से हम निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे है ।

राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कई तरह की सुविधाएं दी हैं। विभिन्न विषयों की पढ़ाई के लिये हजारों की संख्या में शिक्षाकर्मी नियुक्त किये गये शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की कार्यशैली को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण और परिणाममूलक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं। स्कूली बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था दुरूस्त किया गया हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्तमान में प्रथम नागरिक एक महिला है। संसद में लोकसभा का अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस जिनकी वर्तमान में सरकार हैं जिसके अध्यक्ष एक महिला श्रीमती सोनिया गांधी है। भारत के सबसे अधिक विधान सभा और लोकसभा (संख्या की दृ ष्टि से) वाले प्रदेश उत्तरप्रदेश कि सुश्री मायावती बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख हैं। देखा जाए तो भारत की राजनीति में महिलाओं का

योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के विकास के लिए अनेक कार्य किये ।

प्राचीन समय से ही देश के विकास में महिलाओं का योगदान रहा हैं। प्रथम स्वतंतंत्रता संग्राम 1857 की लड़ाई में प्रमुख रूप से रानी लक्ष्मीबाई ने योगदान दिया था जिसकी वीरगाथा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आज भी बच्चों को बताई जाती हैं। तो वहीं रजिया सुल्तान का नाम भी लिया जाता हैं। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक दल कांग्रेस के नाम से बनाया गय था जिसका निर्माण कराने वाली भी एक महिला श्रीमती एनीबिसेंट थी ।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं का राजनीतिक व शैक्षणिक स्थिति उच्च हैं, दुर्ग की महापौर दो बार रह चुकी सुश्री सरोज पाण्डेय ने शीघ्र ही ऊँचाई को छूते हुए विधानसभा और अब लोकसभा तक जा पहुँची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की महापौर श्रीमती किरणमणी नायक एल.एल.बी. व पी.एस.डी. की डिग्री वाली हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर अपना कार्य कर रहा हैं। सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण (पूर्व माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) एवं शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। आपैचारिक एवं औपचारिक के प्रशासकों हेतु नए शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन किया जा रहा हैं। शैक्षिक प्रक्रिया एवं शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति हेतु गुणात्मक सुधार संबंधी कार्य हेतु प्रयासरत है । राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संख्याओं जैसे (NCERT, NUEPA, NGET, RTI, FD, CIC. TELUU) इत्यादि समन्वय किया जा रहा हैं।

पाटन नगर पंचायत की महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकनः–

पाटन में स्थित एक मात्र महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. श्रीमती राधा पाण्डेय है, वही एक मात्र प्राध्यापक डॉ. शोभा श्रीवास्तव है । पाटन में दो प्रमुख स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय के प्राचार्य भी महिला है। माध्यमिक वे प्राथमिक स्कूलों में भी प्रधान अध्यापक के पद पर महिलाओं का वर्चस्य है। जहाँ पर शिक्षा के प्रमुख

पदों पर महिलाओं का वर्चस्व है वहाँ पर महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति की उच्चता का अंदाजा लगाया जा सकता हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता हैं। निवासियों के अनुसार जिस प्रकार से सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है उसी तरह निजी स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए।

नगर पंचायत के द्वारा निजी स्कूल के सुविधाओं व विकास के लिए कार्य करना चाहिए। नगर पंचायत के द्वारा महिला शिक्षा में सुधार कार्य के लिए बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों में भी जागरूकता होना चाहिए तभी पाटन नगर पंचायत की महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति उच्चता को प्राप्त करेगी ।